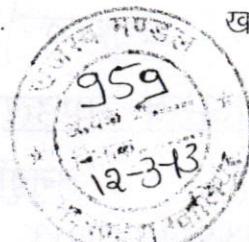


# कायालय कलेक्टर जिला-खण्डवा

संख्या / ३१७८ / वाचक कलां / 2013.

खण्डवा, दिनांक 1.03.2013



विविध 1543-PBR/13

अध्यक्ष,  
राजस्व मण्डल,  
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषय:-

कलेक्टर न्यायालय में संस्थित प्रकरण क्रमांक २-अ-५९/२०११-१२ एवं ३-अ-५९/२०११-१२ में पूर्व पारित आदेशों के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत।

-०:- [शासन | इन्फ्रा स्ट्रक्चर इन्फ्रा इंजिनियरिंग]

खण्डवा जिले का विकास के अंतर्गत परियोजना/ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किये गये एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक दिनांक 19.02.2013 में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स ईरा इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा ग्राम चिंचगोहन, तहसील खण्डवा में 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु मांग की गई शासकीय भूमि से संबंधित संस्थित प्रकरण क्रमांक २-अ-५९/२०११-१२ एवं ३-अ-५९/२०११-१२ में पूर्व पारित आदेशों के पुनर्विलोकन हेतु म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 में विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्ताव विवाद न्यायालय को प्रेषित किए जाए।

2- अ: उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर न्यायालय, खण्डवा में संस्थित राजस्व प्रकरण क्रमांक २-अ-५९/२०११-१२ एवं प्रकरण क्रमांक ३-अ-५९/२०११-१२ में पूर्व पीठारोन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2011 को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति म.प्र.भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा ५१ में उल्लेखित प्रावधान अनुरूप प्रदान करने का कष्ट करें। दोनों मूल राजस्व प्रकरण पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया अनुमति उपरांत मूल प्रकरण वापिस कलेक्टर न्यायालय, खण्डवा को वापिस लौटाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(प्रिया दुबी)

कलेक्टर

जिला, खण्डवा

दूरभाष क्रमांक 0733-2224153

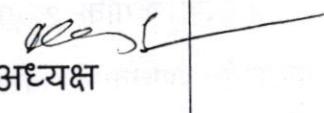
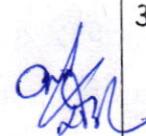
शासन | ३२ इला. इंजी. लि.

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.मिसलेनियस 1543-पीबीआर/2013

जिला-खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-3-2018	<p>आवेदक शासन की ओर से शास0 अधिवक्ता श्री हेमन्त मूंगी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में राजस्व मण्डल को रिव्यु अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारी से रिव्यु अनुमति लेकर आवश्यक कार्यवाही करें।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p> <p></p>	